

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2741
(16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के दायरे को बढ़ाना

2741. श्री अभय कुमार सिन्हा:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) को कृषि से जोड़ने की प्रतिबद्धता के अंतर्गत बिहार के औरंगाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में किये गए कृषि कार्यों का ब्यौरा क्या है और ऐसे कार्यों से लाभान्वित किसानों की संख्या कितनी है;

(ख) इन छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत अब तक पूर्ण किए गए पक्के आवासों की संख्या कितनी है और वर्ष 2025 में बाढ़ पुनर्वास में अभी भी लंबित आवासों की संख्या कितनी है; और

(ग) बिहार बजट 2025-26 के 3.17 लाख करोड़ रुपये में से उपरोक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को ग्रामीण अवसंरचना हेतु कितनी निधि जारी की गई है और इस धनराशि का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मज़दूरी रोजगार योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को मांग के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ दिन का गारंटीकृत अकुशल शारीरिक श्रम रोजगार के रूप में प्रदान करना है जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व की उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन होता है।

औरंगाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत गया और औरंगाबाद जिले का कुछ भाग आता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान गया और औरंगाबाद जिलों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के तहत किए गए कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है:

| वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कृषि और संबद्ध कार्यों का ब्यौरा | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| जिले का नाम | पूर्ण कार्यों की संख्या | वर्ष 2025-26 में कुल व्यय (लाख में) | चल रहे कार्यों की संख्या |
| औरंगाबाद | 2,108 | 7,667.78 | 12,322 |
| गया | 4,813 | 15,814.39 | 29,549 |

गया और औरंगाबाद जिले में किए गए व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है:

| वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत किए गए व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यों का ब्यौरा | | | |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| जिले का नाम | पूर्ण कार्यों की संख्या | वर्ष 2025-26 में कुल व्यय (लाख में) | चल रहे कार्यों की संख्या |
| औरंगाबाद | 295 | 464.56 | 2,994 |
| गया | 1,049 | 646.75 | 4251 |

(ख): ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय दिनांक 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि मार्च 2029 तक बुनियादी सुविधा प्रदान करके 4.95 करोड़ पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके। दिनांक 11.12.2025 की स्थिति के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 4.14 करोड़ (बिहार के लिए 50,12,752) आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिनमें से 3.86 करोड़ (बिहार के लिए 49,08,262) आवासों को मंजूरी दी जा चुकी है और 2.92 करोड़ (बिहार के लिए 39,36,854) आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।

औरंगाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के छह विधानसभा क्षेत्रों में निर्मित किए गए पक्के आवासों की संख्या तालिका 1 में दी गई है। वर्ष 2025 में बिहार राज्य को बाढ़ पुनर्वास के तहत पीएमएवाई-जी के तहत कोई आवंटन नहीं किया गया था।

तालिका-1

| क्र. सं. | विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम | स्वीकृत आवास | निर्मित आवास |
|----------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | औरंगाबाद | 19862 | 17127 |
| 2 | गुरुआ | 25105 | 21306 |
| 3 | इमामगंज | 36893 | 33253 |
| 4 | कुटुम्ब | 13786 | 12082 |
| 5 | रफीगंज | 28891 | 23997 |
| 6 | टिकारी | 24225 | 19592 |
| | कुल | 1,48,762 | 1,27,357 |

(ग): यह मामला बिहार सरकार से संबंधित है। ये आँकड़े केंद्र सरकार स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।